

संपादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अभियान प्रवासी विरोधी बनता जा रहा है। यूएस की टेक कंपनियों को उनकी ताजा चेतावनी इसी का प्रमाण है। हालांकि ट्रंप की ऐसी हर कोशिश उनके ही देश को नुकसान पहुंचाएगी। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही धमकियों से करने वाले ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां केवल अमेरिकियों को ही नौकरी दें। एक एआई समिट में उन्होंने कहा, ‘हमारी कई बड़ी टेक कंपनियों ने

ऐतिहासिक डील के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना आवश्यक है । यह वास्तव में मोदी सरकार का सराहनीय कदम है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, जो लगभग चार-पांच वर्षों से बातचीत में अटका हुआ था, आखिरकार फलीभूत हो गया है। दोनों देश पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन के तहत हस्ताक्षर करने के बहुत करीब थे । जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने थे । लेकिन उससे पहले जॉनसन को जाना पड़ा । बाद में ऋषि सुनक ने भी इसे करने की कोशिश की । इस समझौते का दीप निवास पर दीपावली पर जलाया जाना था । ऐसा नहीं हुआ । फिर चुनाव हुए, और इंग्लैंड में सत्ता लंबे समय से लेबर पार्टी की थी । पूर्व के सभी पक्षपातपूर्ण हैं । पीयूष गोयल मतलब यह सब नए सिरे से शुरू करने के बारे में हैं । प्रधानमंत्री की र स्टार ने ऐसा किया । इसका कारण ब्रिटेन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था है । ऐसे समय में जब ब्रेक्सिट का ग्रहण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को गहरा कर रहा है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का उदय इस ग्रहण के आर्थिक अंधेरे को जोड़ रहा है, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ठोस करने की आवश्यकता है ।

ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को पीयूष गोयल ने बताया गेमचेंजर

अशोक भाटिया

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक डील हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध का नया अध्याय शुरू होगा। 24 जुलाई, 2025 को लंदन में भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देश आपसी व्यापार को 2030 का यानि अगले चार-पांच सालों में 120 अरब यूएस डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट से निकल जाने के बाद पहली बार किसी देश के साथ इतनी बड़ी डील की हो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत की मजबूत और निर्णायक नेतृत्व क्षमता, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और लोगों की बढ़ती आय ने भारत को वैश्विक साझेदार के रूप में एक पसंदीदा देश बना दिया है। यह एक गेमचेंजर समझौता है । यूनाइटेड किंगडम के माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यह यूके का ब्रेक्जिट के बाद का सबसे महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है।

ऐतिहासिक डील के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई देना आवश्यक है । यह वास्तव में मोदी सरकार का सराहनीय कदम है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, जो लगभग चार-पांच वर्षों से बातचीत में अटका हुआ था, आखिरकार फलीभूत हो गया है। दोनों देश पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन के तहत हस्ताक्षर करने के बहुत करीब थे। जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने थे। लेकिन उससे पहले जॉनसन को जाना पड़ा। बाद में ऋषि सुनक ने भी इसे करने की कोशिश की। इस समझौते का दीप निवास पर दीपावली पर जलाया जाना था। ऐसा नहीं हुआ। फिर चुनाव हुए, और इंग्लैंड में सत्ता लंबे समय से लेबर पार्टी की थी। पूर्व के सभी पक्षपातपूर्ण हैं। पीयूष गोयल मतलब यह सब नए सिरे से शुरू करने के बारे में है। प्रधानमंत्री की र स्टार ने ऐसा किया । इसका कारण ब्रिटेन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसे समय में जब ब्रेक्सिट का ग्रहण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को गहरा कर रहा है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का उदय इस ग्रहण के आर्थिक अंधेरे को जोड़ रहा है, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ठोस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, स्टार ने यूरोपीय संघ के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और अब भारत के साथ। उन्होंने यूरोप के साथ समझौते को दोनों के लिए और भारत के लिए जीत का सौदा बताया। आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा इंग्लैंड कुछ ऐसा चाहता था। उन्हें जरूरत अनुबंधों के माध्यम से मिला। यह हमारी जरूरत

भी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने प्रधानमंत्री के आजीवन मित्र रहे डोनाल्ड ट्रंप को एक मुश्किल जगह पर दर्द महसूस होने लगा है। इसके अलावा चीन जो दुविधा पैदा कर रहा है, वह भी है। इन दोनों देशों को छोड़कर यूरोप के साथ व्यापार समझौता भी अधर में लटका हुआ है। ना कहने के लिए, हमने अब तक 14 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन जब संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मॉरीशस, मलेशिया, चिली,



अफगानिस्तान, आदि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम के विकल्प नहीं हैं, तो हमें एक मजबूत व्यापार समझौते की आवश्यकता थी जो दोनों की जरूरतों को पूरा करता हो। इससे अगले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 12 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। वर्तमान में, भारत ब्रिटेन से आयात से अधिक निर्यात करता है। लेकिन फिर भी उस देश के बाजार में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत भी नहीं है। यह अब बढ़ेगा, क्योंकि इस समझौते में, लगभग सभी भारतीय वस्तुओं पर शुन्य प्रतिशत कर लगाया जाएगा। ताकि वे कर-मुक्त हों। कपड़ा, कोल्हापुरी चप्पलें, आप उस देश में अधिक थोक दवाएं / रसायन, आभूषण आदि बेच सकेंगे। साथ ही लक्जरी कारों, महंगी शराब, गैर-कानूनी सेवाओं को इंग्लैंड से भारत में अधिक स्वतंत्र रूप से आपूर्ति की जाएगी। आप इंग्लैंड के सबसे बड़े चांदी आयातक होंगे। इस समझौते के बाद, ब्रिटेन के चांदी के लेनदेन भारत में चांदी के हो जाएंगे। भारत से दो प्रमुख मुद्दे उस देश में भारतीय शराब की मुक्त गुंजाइश और साथ ही, उस देश में शराब की बिक्री थे। इसे भारतीयों के कप में आसानी से गिरने दें। यह कुछ हद तक आसान होगा। कुछ हद तक, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश शराब पर भारत में लगाया गया आयात कर सिर्फ एक मुद्दा है।

आयात कर कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही इससे केंद्रीय और राज्य उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर आदि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समझौते का लाभ शराब कंपनियों की तुलना में शराब कंपनियों को अधिक होगा। उनके लक्जरी कारों के कारण, केवल 350 रुपये में बेची जाने वाली व्हिस्की की बोतल भारतीय बाजार में 3100 रुपये से अधिक महंगी होगी। नए समझौते से मुश्किल से 300 रुपये का अंतर आएगा। दूसरा मुद्दा भारतीय बाजार में कानूनी सलाह देने वाली ब्रिटिश कंपनियों को मुफ्त



दरवाजा देना होगा। 2035 तक, ब्रिटिश कानून फर्मों को भारत में सहायक कंपनियां स्थापित करने की अनुमति देने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। यह कल जा सकता है कि हमने कुछ दिया है, व्यापार के संदर्भ में बहुत कुछ लिया है। हालांकि, इस समझौते का असली फायदा ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को होगा। शिक्षकों, खानसेम और यहां तक कि बड़ी संख्या में हाल के योग गुरुओं को उस देश में अधिक अवसर मिलेंगे। भारतीय तकनीशियनों और कंप्यूटर विशेषज्ञों को मुफ्त में वीजा दिया जाएगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। इसे शुद्ध लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं? यह प्रश्न। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो विदेश जाना चाहते हैं। वह किसी भी पद पर विदेश जाने के लिए उत्सुक है। इंग्लैंड के पास अब उन लोगों के लिए अधिक अवसर होंगे जो ऐसी मातृभूमि को त्यागना चाहते हैं। भले ही यह प्रवासी वर्ग उस देश में रहकर पाउंड में कमाता हो, और अधिक जोश के साथ भारत माता का जाप करें! इसलिए अंतिम लाभ इंग्लैंड को होगा। वह भी दोगुना। एक, जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके कदम इंग्लैंड की ओर मुड़ जाएंगे, और दूसरा, इंग्लैंड को कम पैसे में बड़ी संख्या में अच्छे कुशल श्रमिक / कारीगर

मिलेंगे। देश को पूर्वी यूरोपीय अकुशल भारतीयों की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा लेकिन कुशल भारतीय मिलने लगेंगे जो वहां बहुत सस्ते में आना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे बौद्धिक नुकसान से ब्रिटेन को फायदा होगा। इस प्रकार, ऐसे समय में जब इस मुक्त व्यापार समझौते का जश्न मनाया जा रहा है और यह माना जाता है कि हमने विश्व नेता बनने की दिशा में एक कदम उठाया है, दो बिंदुओं पर ध्यान देना बुद्धिमान है।

पहला बिंदु हमारे निर्यात कारक हैं। पारंपरिक आभूषण और कम कुशल सामग्री हमारी निर्यात सूची में मुख्य योगदानकर्ता हैं। उस समय, यूके आपको जो सामान निर्यात करता है, उनमें उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण, विमान, आदि पुर्जे/प्रौद्योगिकी और समृद्ध कारें शामिल हैं। उन सभी को उच्चतम स्तर की प्रौद्योगिकी और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उनकी लागत भी अधिक होती है। ताकि जो सामान हम उस देश में भेजने जा रहे हैं वह अपेक्षाकृत सस्ता हो और साथ ही उस देश से हमारे बाजार में आ सके। हालाँकि, सामग्री अधिक मूल्यवान होती है। इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड आपको अधिक सामान बेचकर जितना मिलेगा उससे बहुत कम बेचकर उतना ही या उससे अधिक कमाएगा। अर्ध-हमें अधिक निर्यात योग्य कीशल-आधारित वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पापड़ - कुर्द/अचार/पापड़ हीन भावना के नहीं हैं। लेकिन आपको इसके साथ भव्य इंजीनियरिंग का सपना देखने की भी जरूरत है।

उदाहरण के तौर पर, यूके हर साल लगभग 30 बिलियन डॉलर के टेक्सटाइल आयात करता है, जिसमें भारत का हिस्सा सिर्फ 1173 बिलियन डॉलर (करीब 515ब) है। इसका कारण यह था कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश शून्य शुल्क पर निर्यात कर पा रहे थे और भारत प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। अब भारत को भी शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे हमारे उद्योगों को भारी अवसर प्राप्त होंगे। चमड़ा और फुटवेयर उद्योग में भी इयूटी दरें 216 प्रतिशत तक थीं और हमारा निर्यात सिर्फ 015 बिलियन डॉलर था। अब हमारी कोल्हापुरी चप्पलें और जूते यूके बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होंगे। जेम्स और जूलरी जैसे क्षेत्रों में भी जहां 4ब इयूटी लगती थी, अब वह खत्म हो जाएगी।समुद्री उत्पाद, मैकेनिकल मशीनरी, प्लास्टिक, रबर, प्रोसेस्ड फूड्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गूड्स, मीट, फल, सब्जियां, मसाले आदि सभी क्षेत्रों को शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। इससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा और निर्यात में आपत्ता दित वृद्धि हो सकती है।

इंडस्ट्री या सिलिकॉन वैली आज अगर वैश्विक स्तर पर राज कर रही है, तो इसमें प्रवासियों का बड़ा योगदान है। दुनियाभर की मेधा, खासकर भारत की, ने मिलकर इस इंडस्ट्री को सींचा है।

इलॉन मस्क की टेस्ला को जब ऑटोपायलट सॉफ्टवेयर में सफलता मिली, तो उन्होंने भारतीय मूल के एक रोबोटिक्स इंजीनियर अशोक एल्लुस्वामी का ही नाम पहले लिया था। ट्रंप उस वैश्वीकरण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है। उनके पास इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने लायक वर्कफोर्स नहीं है। भारत के बिना उनका मैगा पूरा नहीं हो सकता।

विदेशी चिकित्सा डिग्री : भारत का एनएमसी लगभग 9 लाख रुपये मान्यता शुल्क पेश करता है

विजय गर्ग
भारत के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक नेशनल मेडिकल कमीशन विदेशी चिकित्सा योग्यता को पहचानने के लिए अपने नियमों में एक महत्वपूर्ण फेरबदल की घोषणा की है। एक प्रमुख प्रस्ताव विदेशी विश्वविद्यालयों या उनकी मान्यता एजेंसियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले . 10,000 (लगभग 8.6 लाख रुपये) शुल्क की शुरुआत है, प्रत्येक आवेदन के लिए भारत के मेडिकल कोर्स की आधिकारिक मान्यता की मांग की जाती

यह नीति अनुमानित 20,000 से 25,000 भारतीय छात्रों को सीधे प्रभावित करती है जो सालाना विदेशों में चिकित्सा डिग्री हासिल करते हैं, अक्सर भारत में सीमित एमबीबीएस सीटों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण रूस, चीन, जॉर्जिया और किर्गिस्तान जैसे गंतव्यों का चयन करते हैं। जबकि व्यक्तिगत शुल्क को हटाने से स्नातकों को लौटने के लिए एक वित्तीय बाधा कम हो जाती है, विदेशी संस्थानों पर . 10,000 शुल्क लगाने से संभावित रूप से दूर्यून या प्रशासनिक शुल्क के माध्यम



यह संशोधन औपचारिक रूप से 16 जुलाई, 2025 को एक मसौदा गजट अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया गया था । भारतीय उम्मीदवारों को सीधी राहत प्रदान करने वाले एक कदम में, एनएमसी ने एक साथ पहले से अनिवार्य 2.5 लाख रुपये आवेदन शुल्क को रद्द कर देने का फैसला किया है जो व्यक्तिगत भारतीय डॉक्टरों को अपनी विदेशी चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए भुगतान करना था । एनएमसी भारत में उच्च चिकित्सा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहा है।

यह संशोधन औपचारिक रूप से 16 जुलाई, 2025 को एक मसौदा गजट अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया गया था। भारतीय उम्मीदवारों को सीधी राहत प्रदान करने वाले एक कदम में, एनएमसी ने एक साथ पहले से अनिवार्य 2.5 लाख रुपये आवेदन शुल्क को स्कैप करने का फैसला किया है जो व्यक्तिगत भारतीय डॉक्टरों को अपनी विदेशी चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए भुगतान करना था। एनएमसी भारत में उच्च चिकित्सा इमेल आईडी के माध्यम से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए 30-दिवसीय सार्वजनिक परामर्श अवधि खोली है, जो अंतिम नियामक ढांचे को आकार देने में हितधारक सगाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस मुखर रुख का उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए समान रूप से योग्य चिकित्सा कार्यबल सुनिश्चित करना है।

संशोधन के लिए अप्रत्यक्ष लागत समायोजन हो सकता है। एनएमसी की पहल विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसमें कड़े विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनियम और एफएमजीआई (विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा) जैसी अनिवार्य स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही राष्ट्रीय निकास परीक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। आयोजन ने एक समर्पित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहा है। शुल्क मान्यता प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और सुव्यवस्थित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी योग्यताओं को मान्यता दी जाए। यह दृष्टिकोण भारत को अंतरराष्ट्रीय वरीयता के साथ स्रेखित करता है, जहां अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देशों में समान मान्यता शुल्क आम है।

मदद देकर दुश्मन खड़ा करना कोई मोदी से सीखें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा से जुडी एक खबर बहुत ही लोमहर्षक है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, सांप को दूध पिलाने जैसी है, हिंसकों को संरक्षण और संवर्द्धन करने जैसी है, स्वयं के लिए भस्मासुर खड़े करने जैसी है और भारतीय हितों के खिलाफ है । हालांकि भारतीय मीडिया ने इस पर विचारण के लिए दूरदृष्टि नहीं अपनायी । अब यहां यह प्रश्न उठता है कि वह खबर क्या है? खबर यह है कि मालदीव को भारत पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता देगा, जिसकी घोषणा नरेन्द्र मोदी ने अपनी मालदीव यात्रा के दौरान की है । पांच हजार करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं है, यह बहुत बड़ी रकम है । इतनी बड़ी रकम मालदीव पर खर्च करने की जरूरत ही क्या है? इस विषय को हम किस दृष्टिकोण से देखे ?

आचार्य श्रीहरि
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा से जुडी एक खबर बहुत ही लोमहर्षक है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, सांप को दूध पिलाने जैसी है, हिंसकों को संरक्षण और संवर्द्धन करने जैसी है, स्वयं के लिए भस्मासुर खड़े करने जैसी है और भारतीय हितों के खिलाफ है। हालांकि भारतीय मीडिया ने इस पर विचारण के लिए दूरदृष्टि नहीं अपनायी। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि वह खबर क्या है? खबर यह है कि मालदीव को भारत पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता देगा, जिसकी घोषणा नरेन्द्र मोदी ने अपनी मालदीव यात्रा के दौरान की है। पांच हजार करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं है, यह बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम मालदीव पर खर्च करने की जरूरत ही क्या है? इस विषय को हम किस दृष्टिकोण से देखे?

मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश भी सुख और शांति से रहे, इसकी इच्छा तो रखनी चाहिए। पर प्रश्न यह उठता है कि जो देश हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो गया है, जिसके लिए धर्म्मनिरपेक्षता कोई अर्थ नहीं रह गयी है, जिसकी नीयत हिंसक हैं, आतंकी है और स्वयं को असफल देश के गर्त में ढकेलने में लगा रहता है उसके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने का काम सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। दुनिया में सिर्फ भारत ही एक मात्र देश है जो अपने हिंसक और अलोकमात्रिक पड़ोसी देशों को भी अरबों-खरबों रुपये देकर पालता है। जबकि चीन और अमेरिका जैसे देश कर्ज के मकड़जाल में फंसा कर लुटते है और अपने हित सुरक्षित रखते हैं, विकसित करते हैं। चीन ने श्रीलंका को कर्ज देकर दिवालिया बना कर छोड़ा। चीन ने पाकिस्तान को भी कर्ज के दबाव में जकड़ चुका है। यूक्रेन की मदद

के लिए अमेरिका ने खनिज संपदा समझौता किया है, जिसके तहत यूक्रेन के खनिज संपदाओं का दोहन अमेरिका करेगा। मालदीप तो एक विलुप्त होता देश है जो परजीवी है पर हिंसक और मजहबी मामलों में पाकिस्तान-सीरिया के रास्ते पर चल रहा है।

नरेन्द्र मोदी का ऐसा कदम सहानुभूति तो प्रकट कर सकता है, उन्हें लोग दयावन तो समझ सकते हैं, उन्हें पड़ोसियों को मिला कर, खुश रखकर चलने वाला शासक कह सकते हैं। लेकिन भारत की इस सहायता का सकारात्मक उपयोग होगा, जनपक्षीय उपयोग होगा, पारिस्थिति के संरक्षण में उपयोग होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत के धन से मालदीव अपनी मजहबी मानसिकता का भी पोषण करेगा, आतंकियों का संरक्षण और उनका संवर्द्धन भी कर सकता है? ऐसी समझ रखना कोई गैर जरूरी बात नहीं हो सकती है। मालदीव को अब पर्यटन से होने वाली आय कम हो गयी है, इसलिए उसे मजहबी मानसिकता की तुष्टि के लिए और प्रचार-प्रसार के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत है। इसीलिए मालदीव अपने आप को बदलने का नाटक कर रहा है और भारत के मित्र होने का दावा कर रहा है।

सच यह है कि मालदीव हमारा दोस्त भी नहीं है, मालदीव हमारे लिए अच्छा पड़ोसी भी नहीं है। मालदीव कोई आदर्श सूचक देश भी नहीं है। मालदीव में धर्म्मनिरपेक्षता भी नहीं है। पूरी आबादी मजहबी मानसिकता में विश्वास करती है। कुछ नाम मात्र के अन्य धर्म्म के लोग मालदीव में रहते हैं, उनका कोई मानवाधिकार का संरक्षण नहीं होता, उनकी धार्मिक मान्यताएं प्रतिबंधित हैं। इस्लाम की सनहर आबादी को छोड़ कर अन्य कोई आबादी अपनी धार्मिक मान्यताओं का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ

यह है कि मालदीव पूरी तरह से इस्लामिक कट्टर मानसिकताओं की हिंसक प्रवृत्ति में कैद हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और लेबानन, सीरिया जैसी मजहबी मानसिकताएं अपना प्रदर्शन करती हैं। वैश्विक मीडिया में कई अन्य हिंसक तथ्य भी अस्तित्व में हैं। खासकर अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अलकायदा और तालिबान के कई खतरनाक और हिंसक आतंकी मालदीव में संरक्षण लिये थे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार स्थापित हो गयी, इस कारण तालिबान के आतंकियों की अब मजबूती समाप्त हो गयी, उनके मालदीव में रहने और सक्रिय होने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर समस्याएं बहुत ही खतरनाक है और हिंसक है। पाकिस्तान का आईएसआई का मकड़ जाल फैला हुआ है। आईएसआई के अधिकारी और जासूस मालदीव में बैठे हुए हैं और वे तय कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में मालदीव का इस्लामिक करण मजबूत रहे। आईएसआई का भारत के खिलाफ दृष्टिकोण और कार्ररानी भी जगजाहिर है। भारत के खिलाफ आईएसआई ने न केवल साजिशें रचती है बल्कि मालदीव की आबादी को भड़काती भी है। आईएसआई हमेशा भारतीय हितों को हिंसक ढंग से कुचलती है और कहती है कि भारत मालदीव का हिन्दूकरण करने जा रहा है और भारत मालदीव को अपना गुलाम बनाना चाहता है,इसलिए भारत का विरोध अनिवार्य है। मालदीव का सत्ता राजनीति आईएसआई का मोहरा है।

मालदीव ने भारत को कितने घाव दिये हैं, कितनी लातें मारी है, भारत के हितों को कितना कुचला है, भारत के सम्मान को कितना नुकसान पहुंचाया है? यह सब किसे नहीं मात्तूम है। मालदीव में हमारा सैनिक अड्डा था। ऐसे मालदीव

सैनिक अड्डे के लिए कोई खास महत्व नहीं रखता है। फिर भी हमारा सैनिक अड्डा था। हम उस सैनिक अड्डे का उपयोग अपने हितों की रक्षा करने के लिए कर रहे थे। खासकर चीन की सैनिक गतिविधियों और सक्रियता को लेकर हमारी चिंता रही है। चीन ने समुद्र में कई प्रकार की गतिविधियां, समस्याएं और अड़चने खडी की है। अपनी आधुनिक नौकाओं के माध्यम से चीन की नजर भारत की महत्वपूर्ण सैनिक अड्डो पर रही है।

चीन अपनी आधुनिक नौकाओं के माध्यम से हमारी जासूसी भी करता है। इसलिए मालदीव में मजबूत भारतीय सेना का ठिकाना अति महत्वपूर्ण था। सबसे बडी बात सैनिक अड्डे पर विराजमान भारतीय सैनिक मालदीव की एकता और अखंडता के लिए कोई चुनौती नहीं थे। फिर भी पाकिस्तान और चीन को वह हमारा सैनिक अड्डा खटकता था। चीन और पाकिस्तान की के कहने पर मालदीव ने भारतीय सैनिक अड्डे को समाप्त करने के लिए भारत को बाध्य किया। भारत के खिलाफ हिंसक और तथ्यहीन बयानबाजी की गयी। कोई विकल्प न देखते हुए भारत की मोदी सरकार ने ही सैनिक अड्डे से अपने सैनिक हटाने का काम किया था। सबसे बडी बात मोदी की छवि और सम्मान पर कीचड़ उछलाना और कूटनीतिक सम्मान को भूल जाना। नरेन्द्र मोदी कभी भी मालदीव के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। सिर्फ उसने अपने देश के पर्यटक स्थलों का प्रमोशन किया था। नरेन्द्र मोदी ने लक्ष्यद्वीप की यात्रा की थी। लक्ष्यद्वीप एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, उसकी खूबसूरती मालदीव के पर्यटक स्थलों से कम नहीं है। नरेन्द्र मोदी लक्ष्यद्वीप जाकर पर्यटक स्थलों का दर्शन कराया था। इस पर मालदीव की पूरी सरकार ही पागल हो गयी, हिंसक हो गयी, मालदीव सरकार में शामिल मंत्रियों ने नरेन्द्र मोदी को गालियां दी थी, नरेन्द्र मोदी को नीच कहा था और भारत को बर्बाद करने को धमकी पिलायी थी।

संक्षिप्त समाचार

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान
की राशि नहीं जमा करने पर 1 माह
15 दिन की कारावास



मूक पत्रिका/दत्तेवाड़ा - पुलिस अधीक्षक गौरव राय (भा.पु.से.) के निदेशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात नमर उल्लाह सिद्दिकी के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र त्रिपाठी के हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक साध सिंह देशमुख आरक्षक आदित्य कंदौड़ी, हेमलाल रावते, वीरेंद्र कुमार वर्मा एवं यातायात की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27/07/25 को वाहन चेकिंग के दौरान गायत्री चौक दत्तेवाड़ा में ट्रक चालक आधिपत्य वाहन क्रमांक झर 29 झर्र 5679 को प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बिना मूल दस्तावेज के वाहन चलाने पर माननीय सीजेएम न्यायालय दत्तेवाड़ा प्रस्तुत किया गया जहां पर न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने एवं मूल दस्तावेज पेश नहीं करने पर ट्रक चालक याकूब पासा पिता एच डी रहीम उम्र 29 वर्ष साकिन भद्राद्री तेलंगाना को ? 22100 के अर्थ दंड से दंडित किया गया परंतु ट्रक चालक द्वारा अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर न्यायालय द्वारा 01 माह 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में
डॉ. मेघेश तिवारी हुए, सम्मानित



मूक पत्रिका/ बेमेतरा/देवकर - सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में दंडी श्रीमज्ज्योतिष्यानंद सरस्वती महाराज के द्वितीय दिव्य चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान के अवसर पर रविवर के कार्यपरिषद के वरिष्ठ सदस्य एवं वरिष्ठ कालिंज के संस्थापक प्राचार्य, डॉ. मेघेश तिवारी का शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉ. मेघेश तिवारी वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश तिवारी के बड़े भाई हैं। सलधा में दंडी श्रीमज्ज्योतिष्यानंद सरस्वती महाराज के द्वितीय दिव्य चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान अवसर पर आयोजित समारोह में सरस्वती महाश्री ने अतिरिक्त पत्र से सम्मानित किया। सम्मान से अभिभूत डॉ. मेघेश तिवारी ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब सम्मान के रूप में दंडी स्वामी श्रीमज्ज्योतिष्यानंद सरस्वती महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। उनके करमलानों प्राप्त सम्मान से शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए नवीन उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है।

सतनाम भवन नवागढ़ में ममतामयी
मिनी माता पुण्यतिथि की आयोजन
तैयारी को लेकर बैठक संपन्न



मूक पत्रिका/ बेमेतरा/नवागढ़ बीते शुक्रवार को सतनाम भवन नवागढ़ में समतामयी मिनी माता की पुण्यतिथि समारोह का भव्य तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस आयोजन को ऐतिहासिक और गरिमामयी स्वरूप देने हेतु समाज के प्रबुद्ध जनों ने संविधान भागीदारी निभाई और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचारों से चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने आयोजन की सम्वत्ता के लिए समाजजनों को मार्ग प्रशस्त किया तथा आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। सभी समाजबंधुओं ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समजप्रति भाव से सहयोग और मार्गदर्शन देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को लेकर समाज में उत्साह का वातावरण है।

पूक पत्रिका/ दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचरक भर्ती परीक्षा का आयोजन आगामी 3 अगस्त 2025, रविवार को दंतेवाड़ा जिले में किया जाएगा। परीक्षा प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में जिलेभर से कुल 772 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को सुचारु, पारदर्शी और शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली हैं। इस संबंध में प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं बिजली विभाग

को आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए उड़नदस्ता दल तथा निरीक्षक (ऑब्जर्वर) भी नियुक्त किए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान अनुशासन एवं निष्पक्षता बनाए रखने में सहयोग करेंगे।

परीक्षा के लिए जिले में तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतवाड़ा (कोड 1401), शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दंतवाड़ा (कोड 1402) तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दंतवाड़ा (कोड 1403) शामिल हैं।

ग्राम पंचायत कटुलनार की ग्राम सभा में
स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं स्वच्छता पर आधारित
''व्यवहार कॉर्नर'' पर हुआ विचार विमर्श



पूक पत्रिका **दत्तेवाड़ा** - जिला प्रशासन, यूनिसेफ एवं एलएसए फॉर बिहिवियर चेंज के संयुक्त तत्वाधान में विगत दिवस ग्राम पंचायत कलनगर में आयोजित ग्राम सभा में बालक बालिका शिक्षा एवं अधिभावकों की भागीदारी, के तहत "व्यवहार कॉर्नर", "रूप नहीं गुण को देखो", "आज क्या सीखा", "पढ़ाई का कोना" जैसे विन्दुओं के प्रति पाठकों की भूमिका को बढ़ावा देने अग्रणी कबधेला गया। इस संबंध में जिला सनमयक राजेश बघेल ने बताया कि जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, समग्र शिक्षा एवं यूनिसेफ के सहयोग से ग्राम सभा में "आजकल कॉर्नर" बनाया गया है, जिससे शारीरिक व्यवहार कॉर्नर" बनाया गया है, जिससे शारीरिक आत्म विश्वास एवं स्वस्थ किशोरावस्था में

अधिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। जिले के इस पहले "व्यवहार कॉर्नर" अन्तर्गत समुदाय आधारित बालक बालिका शिक्षा भेदभाव, बाल विवाह, माववारी के दौरान भेदभाव, किशोरावस्था से जुड़ी लैंगिक और शारीरिक बनावट संबंधी भेदभाव को समाप्त करने हेतु पहल की गई। साथ ही नवज्यों को सुरक्षा माहौल के साथ पढ़ाई के लिए प्रेरित करने "आज क्या सीखा", एवं "पढ़ाई का कोना" बनाने हेतु पालकों से आग्रह किया गया। ग्राम सभा में सरपंच, सचिव, वार्ड पंच, शिक्षक, युवोदय विकासखंड समन्वयक, मितानिन, युवोदय स्वयं सेवक, ग्रामीण, समूह की महिलाएं एवं मितानिन उपस्थित रहे।

शीर्षक : हमर भगवान

दाई ददा हे भगवान
 युवा बुर्जुग 'ल होगे ग.सियान
 संज्ञा बिहीनिया करले ग प्रणाम
 दाई ददा के करले ग प्रणाम
 मरे के बाद नई मिलय ग दुबारा ।
 जग मा हवैय ग महान्
 दाई ददा के करले ग परनाम ॥



दाई ददा के पांव पखा रव
 सदा नवाव माथ ल ।
 करलव सेवा सब तर जाहु
 झन छौड़व जी साथ ल ॥
 दया मया ल संगमा राखव
 अकर करलव ग गुण गान ॥
 संझा बिहीनीया करले ग प्रणाम '
 संझा बिहीनीय करले प्रणाम
 दाई ददा के करले ग परनाम ॥

दाई ददा तोर प्रगट देवता
 घर बइठे तै करले सेवा ।
 पथरा मुरती के पूजा छौड़व
 देवी देवता ल घुरवा म गाड़व ॥
 घर बइठे सेवा है महान
 संझा बिहीनिया करले ग प्रणाम
 दाई ददा के करले ग परनाम ॥

दाई ददा ह . ददा बबा सिखाये
 मामा नाना बोले ल सिखाये ।
 हाथ ल धरके रेंगे .ला सिखाये
 गोदी म पाके गली गली घुमाये ॥
 काबर बनत हव ग नदान
 संज्ञा बिहीनिया करले ग प्रणाम
 दाई ददा के करले ग परनाम ॥

कमा कमा 'के कौड़ी कौड़ी ग बचाये
स्कुल भेज के तोला ग पढ़ाये ।
तोला खवाके अपन खाये
पढ़ा लिखा के .तोला गुनवान ग बनाये
पंडित बनेव ग विद्वान
संज्ञा बिहिनिया करले ग प्रणाम
दाई ददा के करले ग परनाम ॥

परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी संयुक्त कलेक्टर भरतराम धुर्वे को सौंपी गई है। उन्हें इस परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। संयुक्त कलेक्टर धुर्वे ने सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षा प्रक्रिया की गिनतानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचेंगे ताकि उनका प्रिस्किंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 15

मिनट पूर्व केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थरियों को हल्के रंग के आधी ब्राह्म वाले कपड़े पहनने एवं पुस्तिवार के रूप में चप्पल पहनने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कानों में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित रहेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केन्द्र से बाहर जाना वर्जित किया गया है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, घड़ी, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि लाने का पूर्णतः वर्जित है।

गोकुलनगर का होगा जीर्णोद्धार
बायो गैस संयंत्र होगा चालू.....

कोरबा। गोकुलनगर स्थित नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा संचालित गोठान का अब जीर्णोद्धार कर उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाएगा, इसके साथ ही गोठान परिसर में स्थापित बायो गैस संयंत्र को भी चालू कराया जाएगा। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने प्रातः भ्रमण के दौरान गोकुलनगर पहुंचकर गोठान का निरीक्षण किया तथा उक्त व्यवस्थाओं के संबंध में त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने गोकुलनगर के निवासियों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की तथा निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय मोलवार का अधिकारियों की टीम के साथ सुबह-सुबह गोकुलनगर पहुंचे, उन्होंने वहाँ पर स्थित गोठान का सघन रूप से निरीक्षण किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा गोकुलनगर में गोठान का संचालन किया जा रहा है, जहाँ पर मवेशियों के ठहराने व उनके खाने-पीने का प्रबंध किया गया है, शहर की सड़कों में स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को सड़कों से उठाकर उक्त गोठान में ही रखा जाता है, वर्तमान में गोठान में 100 से अधिक मवेशी रखे गये हैं। आयुक्त पाण्डेय ने गोठान के निरीक्षण के दौरान पाया कि वर्तमान में वहाँ पर अपेक्षाकृत शेड का संख्या कम है तथा और अधिक संख्या में शेड लगाया जाना आवश्यक है, ताकि गोठान में रखे गये सभी मवेशियों के लिए पर्याप्त छायादार स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार शेड स्थापित किये जाएं तथा सुरक्षा के मद्देनजर बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत व जीर्णोद्धार हेतु निर्देश कार्यवाही की जाए, इसके साथ ही गोठान में अन्य मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य करने एवं वहाँ की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त गोठान परिसर में निगम द्वारा पूर्व में बायो गैस संयंत्र की स्थापना कराई गई थी किन्तु संयंत्र को प्रारंभ नहीं किया जा सका था, आयुक्त पाण्डेय ने उक्त संयंत्र का निरीक्षण किया, की गई व्यवस्थाओं को देखा तथा संयंत्र को चालू करने के संबंध में त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आर.पी.नगर की समस्याएं होंगी दूर - आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने वार्ड क्र. 31 राजेन्द्र प्रसाद नगर के पार्षद अशोक चावलानी एवं अधिकारियों की टीम के साथ वार्ड का सघन रूप से भ्रमण किया, वहाँ की समस्याओं को देखा तथा साथ ही प्रमुख समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान आयुक्त पाण्डेय ने राजेन्द्र प्रसाद नगर फेस-2 रेलवे लाइन के किनारे स्थित कालोनी में जलभराव की समस्या को दूर करने, वहाँ पर स्थित नाले की सफाई, आवश्यक मरम्मत व सुधार कार्य एवं नाले को रोड साईड पर कवर्ड करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि नाले के ओव्हरफ्लो होने के कारण होने वाले जलभराव को समाप्त किया जा सके। आयुक्त पाण्डेय ने शिवाजीनगर की ओर पौड़ीबहार की तरफ जाने वाले मार्ग पर पक्की सड़क बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, वार्ड में स्थित कबीर आश्रम के पास स्थित शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा की कोशिश हो रही है, इसकी शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने उक्त जमीन को सुरक्षित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

कार्यालय, सदभावना महिला संकुल स्तरीय संगठन – मोहंदी
विकासखण्ड मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.)

// आई.एफ.सी. (IFC) एंकर भर्ती विज्ञापन //

एकीकृत फार्मिंग कलस्टर अंतर्गत आई.एफ.सी. (IFC) एंकर ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका संवर्धन हेतु फार्म, ऑफ फार्म, एवं नॉन फार्म आजीविका विभिन्न कार्य जैसे एग्रो इकोलॉजिकल पद्धति, मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार फसल विविधीकरण और उत्पादकता में सुधार एवं एग्रीन्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण में सुधार, पशुधन प्रबंधन, नस्ल में सुधार, समय पर पशु चिकित्सा देखभाल और टीकाकरण को अपना कर महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों मुख्यतः महिला किसानों एवं पशुपालकों के आजीविका स्तर को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सद्भावना महिला संकुल स्तरीय संगठन मोहंदी, विकासखंड मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.) को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्य के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आई.एफ.सी. (IFC) एंकर की भर्ती की जानी है। उक्त आई.एफ.सी. (IFC) एंकर की भर्ती पूर्णकालिन के लिए ही होगी। यह भर्ती पूर्ण रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत गठित सद्भावना महिला संकुल स्तरीय संगठन मोहंदी के स्वामित्व के अधीन होगी। इसका किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी संस्था से कोई संबंध नहीं है।

आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 01.08.2025 व अंतिम तिथि 09.08.2025 शाम 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से पता कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मगरलोट, जिला धमतरी (छ.ग.)- 493662 के पते पर आमंत्रित किया जावेगा। ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आई.एफ.सी. एंकर पद संख्या -01 (अनारक्षित) हेतु आवश्यक अर्हता, मापदण्ड, मानदेय व भत्ता का विवरण -

क्र.	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम कार्यानुभव (वर्ष)	एकमुश्त मासिक मानदेय (रु. में)	यात्रा भत्ता (रु. में)	वांछित अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विषय में स्नातक उपाधि	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता उपरांत फील्ड स्तर पर कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव	30000 /—	3000 /—	यदि कॉलम 2 एवं 3 अनुसार उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होती है तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित स्नातक डिग्री के साथ ग्रामीण स्तर एवं कृषि संबंधित कार्य का 02 वर्ष का अनुभव वांछित। ग्रामीण परिपेक्ष्य एवं मार्केटिंग में कार्यानुभव को प्राथमिकता। हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम। साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। कम्प्यूटर एवं एम.एस.ऑफिस में कार्य करने में दक्ष हो एवं हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग आती हो। रिपोर्ट लेखा एवं डेटा प्रबंधन में दक्षता। क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज सहित स्वयं का वाहन (दो-पहिया)

टीप: विस्तृत जानकारी के लिए बिहान कार्यालय
जनपद पंचायत मगरलोड में संपर्क करें।

अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष
सद्भावना महिला संकुल स्तरीय संगठन मोहंदी
ग्राम बेलोरा (पुराना पंचायत भवन) वि.खं. मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.)

रचनाकार

गणेशमहंत नवलपुरिहा

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कठले द्वारा स्वामी डीबी कार्प लिमिटेड के लिए प्लॉट नम्बर 40/44 इंडस्ट्रियल एरिया बीरगांव रोड, उरला, रायपुर से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित। संपादक आशिष कुमार कठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।